बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 21 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 28 अक्तूबर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

गोदरेज प्रॉपर्टीज को मुंबई में 'गोदरेज ट्रिलॉजी परियोजना से 10 हजार करोड़ से अधिक के राजस्व की उम्मीद

नई दिल्ली । रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज को मुंबई के वर्ली में अपनी आगामी आवासीय परियोजना से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की आय की उम्मीद है। इस 2.63 एकड़ में फैली 'गोदरेज ट्रिलॉजी परियोजना में तीन आवासीय टावर होंगे। पहले चरण में कंपनी इस तिमाही के दौरान दो टावर पेश करेगी। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसे वर्ली स्थित अपनी 'गोदरेज ट्रिलॉजी परियोजना के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (महारेरा) से परियोजना पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है।

सोने में हालिया तेजी से परिवारों की नेटवर्थ तो बढ़ी पर खपत बेअसर, रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली । सोने के दामों में हालिया तेजी ने भारतीय परिवारों की कुल संपत्ति में तो इजाफा किया है, लेकिन इसका उपभोग पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखा है। सिस्टमैटिक्स रिसर्च की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में उछाल से घरेलू संपत्ति कागज पर तो बढ़ गई है, लेकिन इसका असर व्यापक उपभोग वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं दे रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में उपभोग का वास्तविक चालक आय में वृद्धि है। यह पिछले कुछ वर्षों में सुस्त बनी हुई है खासकर कोविड के बाद के-शेप्ड रिकवरी के दौरान। ऐसे में सोने की कीमतों में उछाल के बावजूद खपत में तेज सुधार नजर नहीं आ रहा है। इसमें बताया गया है कि सोने की बढ़ती कीमतें मुख्य रूप से नेशनल वेल्थ इफेक्ट पैदा करती हैं, इसका मतलब है कि सोने का मूल्य बढ़ने से परिवारों की नेट वर्थ तो अधिक दिखाई देती है, लेकिन खर्च तब तक नहीं बढ़ता, जब तक सोने को बेचा न जाए। आमतौर पर परिवार सोना तभी बेचते हैं जब आर्थिक संकट हो, इसलिए यह संपत्ति बढ़ोतरी उपभोग को गति देने में प्रभावी नहीं बन पाती। इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि घरेलू बचत में गिरावट, खुदार ऋण में कमी और आय पर लगातार दबाव जैसे कारक उपभोग वृद्धि को सीमित कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में यह सामने आया है कि भारत में सोने की ऊंची कीमतों के चलते सोने को गिरवी रखकर लोन लेने की संभावना बढ़ गई है। सोने की ऊंची कीमतों ने सोने की होल्डिंग्स की गिरवी (कॉलेटरल) वैल्यू को मजबूत किया है, जिससे यह रिटेल लोन के लिए उपयोगी संपत्ति बन गई है। हालांकि, इस चैनल के होने का अर्थ यह नहीं है कि खपत बढ़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोने पर आधारित लोन वृद्धि आर्थिक संकट का संकेत है, न कि उच्च उपभोग या उपभोक्ता आत्मविश्वास का। विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय परिवारों के पास लगभग 24,000-25,000 टन सोना है। यह दुनिया के कुल सोने का करीब 11 प्रतिशत है।इसके साथ ही, सोने की कीमतों में 2024 के बाद से तेज उछाल ने घरेलू सोने की होल्डिंग्स का मूल्य लगभग 3.24 ट्रिलियन (3.24 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचा दिया है। यह भारत की जीडीपी के लगभग बराबर है यानी घरेलू नेट वर्थ में 100 फीसदी की वृद्धि का संकेत।

धान किसानों के लिए बड़ी खबर

भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन, वैश्विक बाजार से जुड़ने का मौका

नई दिल्ली । भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन (बीआईआरसी) 2025 को विकसित भारत 2047 की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह आयोजन देश के किसानों के हितों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय चावल निर्यातक महासंघ (आईआरईएफ) के अनुसार, यह आयोजन 30 और 31 अक्तूबर 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें देशभर से करीब 5,000 किसान हिस्सा लेंगे। आईआरईएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम गर्ग ने कहा कि बीआईआरसी 2025 में किसानों को शोधाकर्ताओं, निर्यातकों, मिल मालिकों, विदेशी खरीदारों, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं के साथ सीधे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब किसान वैश्विक सप्लाई चेन से इतने बड़े स्तर पर सीधे जुड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे धान उत्पादन में पर्यावरणीय प्रभाव कम किया जा सके। दूसरा, वे गैर-बासमती और बासमती चावल, दोनों की उच्च-मूल्य वाली किस्मों के लिए संभावित खरीदारों से मिल सकेंगे। कई राज्यों और क्षेत्रों में, किसान अभी भी पर्याप्त बाजार मांग पैदा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अक्सर कम दामों पर बेचने को मजबूर होते हैं। बीआईआरसी 2025 में निर्यातकों के साथ सीधे बातचीत करके, वे बिचौलियों पर निर्भरता कम कर सकते हैं और अपनी फसलों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, किसान नई प्रौद्योगिकियों को समझने के लिए स्टार्टअप्स से जुड़ेंगे, जो मिट्टी की स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए पैदावार बढ़ा सकती हैं। बीआईआरसी का आयोजन भारतीय चावल निर्यातक संघ (आईआरईएफ) की ओर से किया जा रहा है।

यह देश के चावल पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध वाणियिक और संस्थागत हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है। इसमें देश भर के 7,500 से अधिक निर्यातक और संबद्ध हितधारक शामिल हैं।

अमेरिका-ब्राजील व्यापार संबंधों में गर्माहट, राष्ट्रपति लूला बोले- ट्रंप ने दी समझौते की गारंटी

नई दिल्ली । ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने सोमवार को कहा कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई मुलाकात के दौरान उन्हें दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति का भरोसा मिला है। लूला ने मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन से इतर बताया कि ट्रंप ने उन्हें गारंटी दी है कि अमेरिका और ब्राजील जल्द ही इस समझौते को अंतिम रूप देंगे। बता दें कि ट्रंप ने अगस्त की शुरुआत में ब्राजील पर लगने वाले 10 प्रतिशत टैरिफ को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया था। ट्रंप ने इस फैसले को ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोलसोनारो के खिलाफ चल रही कथित विज हंट से जोड़ा था। बोलसोनारो को सितंबर में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट पैनल ने 27 साल से अधिक की सजा सुनाई है। उन पर 2022 के चुनाव में लूला दा सिल्वा से हारने के बाद सत्ता पलटने की साजिश रचने का आरोप साबित हुआ। ट्रंप की टैरिफ बढ़ोतरी के फैसले पर लूला ने गलत कहा था। उन्होंने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किसी भी मुद्दा पर चार्चा करने को तैयार हैं और अमेरिका की हर तरह से मदद करने को भी तैयार हैं। लूला ने कहा कि मैंने ट्रंप से कहा कि ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके लगभग सभी पड़ोसी दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं। ऐसे में अमेरिका को उसकी आर्थिक अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह ब्राजील से क्या अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने बैठक में यह बिंदु भी उठाया कि ब्राजील कई अन्य देशों के विपरीत, आमतौर पर अमेरिका के साथ वार्षिक व्यापार घाटे में रहता है और यह बात सहयोग बढ़ाने के लिए ध्यान में रखी जानी चाहिए। राष्ट्रपति लूला ने प्रेस को बताया कि उन्होंने ट्रंप को अगले वर्ष ब्राजील में होने वाले COP30 क्लाइमेट टॉक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

लेंसकार्ट 7278 करोड़ रुपये के आईपीओ के साथ शेयर बाजार में उतरेगी, 10 नवंबर को होगी लिस्टिंग

नई दिल्ली। चश्मा विक्रेता लेंसकार्ट सॉल्यूशंस ने सोमवार को अपने आईपीओ के लिए 382 से 402 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया। कंपनी 69,700 करोड़ रुपये से अधिक के मूल्यांकन का लक्ष्य रख रही है। लेंसकार्ट का शेयर 10 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। लेंसकार्ट के 7,278 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के लिए बोलियां 31 अक्तूबर से 4 नवंबर तक आम निवेशकों के लिए खुलेंगी। वहीं एंकर निवेशकों के लिए बोली 30 अक्तूबर को एक दिन के लिए खुलेगी। लेंसकार्ट का यह पहला पब्लिक ऑफर 2,150 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू और 12.75 करोड़ से यादा शेयरों के ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) से मिलकर बना है। ओएफएस के तहत प्रमोटर्स पीयूष बंसल, नेहा बंसल, अमित चौधरी और सुमीत कपाही व कई बड़े निवेशक अपने हिस्से का हिस्सा बेचेंगे। इनमें एसवीएफ II लाइटबल्ब (केमैन) लिमिटेड, श्रोडर्स कैपिटल प्राइवेट इक्विटी एशिया मॉरीशस लिमिटेड, पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड II, मैक्रिची इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, केदारा कैपिटल फंड II एलएलपी व अल्फा वेव वेंचर्स एलपी भी शामिल हैं।

लेंसकार्ट आईपीओ से प्राप्त हुई राशि का उपयोग विभिन्न रणनीतिक पहलों के लिए करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें भारत में नए कंपनी-ऑपरेटेड, कंपनी-ओन्ड (कोको) स्टोर्स खोलने के लिए कैपेक्स, इनके लीज, किराया और लाइसेंस से जुड़े भुगतान शामिल हैं। साथ ही एक हिस्सा टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड मार्केटिंग व बिजनेस प्रमोशन, संभावित इनऑर्गेनिक अधिग्रहण और जनरल कॉर्पोरेट जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। बीते हफ्ते खबर आई थी कि अरबपति निवेशक और डीमार्ट के संस्थापक राधाकिशन दमानी ने प्री-आईपीओ राउंड में करीब 90 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

लेंसकार्ट देश की सबसे बड़ी ओमनी-चैनल आईवियर रिटेलर्स में से एक है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विस्तृत रिटेल नेटवर्क के जरिए किफायती और फैशनेबल आईवियर ऑफर करती है। कंपनी का उत्पाद पोर्टफोलियो प्रिस्क्रिप्शन चश्मे, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस तक फैला है। 2008 में स्थापित लेंसकार्ट ने 2010 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर शुरुआत की और 2013 में दिल्ली में पहला फिजिकल स्टोर लॉन्च किया। आज यह भारत की आईवियर कैटेगरी में एक प्रमुख कंयूमर ब्रांड बन चुकी है। कंपनी की मौजूदगी मेट्रो, टियर-1 और टियर-2 शहरों के साथ-साथ साउथ-ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक है।

हरे निशान पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 270 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी तेजी

नई दिल्ली । बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी आई। यह वैश्विक बाजारों में आई तेजी को दर्शाता है, क्योंकि अमेरिका में उम्मीद से कमजोर मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने फेड ब्याज दरों में कटौती की संभावना को फिर से जगा दिया है। साथ ही अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावनाओं और नए विदेशी पूंजी प्रवाह ने भी बाजार की आशा को बढ़ाया। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 9:27 तक 270.76 अंक 0.32 या प्रतिशत उछलकर 84,482.64 पर आ गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 85.0 अंक या 0.33 प्रतिशत उछलकर 25,880.15 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और एनटीपीसी प्रमुख लाभ में रहीं। वहीं इंफोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस पिछड़ गए। एशियाई बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग तेजी से ऊपर कारोबार कर रहे थे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए।

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि वैश्विक बाजार का रुख तेजी का है। डाउ जोंस, निक्केई और कोस्पी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने से धारणा सकारात्मक है।

वैश्विक स्तर पर, व्यापार तनाव में कमी के संकेत मिल रहे हैं। मेहता लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (अनुसंधान) प्रशांत तापसे ने कहा कि अमेरिका में मुद्रास्फीति की उम्मीद से कम रिपोर्ट ने फेड ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अमेरिका-चीन व्यापार समझौते की संभावना और भारतीय आयातों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ में 15-16 प्रतिशत की कटौती की संभावना से आशावाद में और वृद्धि हुई है। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.23 प्रतिशत बढ़कर 66.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 621.51 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे। शुक्रवार को सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,211.88 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 96.25 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,795.15 पर बंद हुआ।

बिहार चुनाव - एक नया मोड़ या वही राह?

बिहार की राजनीति हमेशा से प्रयोगों, व्यक्तियों और गठबंधनों की धरती रही है। यहां सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ वोटों से नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, जातीय गणित और जनभावनाओं से होकर गुजरता है। अब जब 2025 के विधानसभा चुनावों की दस्तक हो चुकी है, पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है। यह चुनाव न केवल राज्य की राजनीति को, बल्कि राष्ट्रीय समीकरणों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बार मुकाबला दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण इसलिए है, क्योंकि मैदान में तीन धाराएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। 'इंडिया' गठबंधन, जिसमें मुख्य भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) है। एनडीए, जिसमें जनता दल (यू) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार केंद्र में हैं वहीं, तेजी से उभरती शक्ति के रूप में प्रशांत किशोर का 'जन सुराज अभियान'। राजद की अगुवाई वाला 'इंडिया' गठबंधन इस चुनाव को अपनी साख बचाने के साथ-साथ केंद्र की राजनीति में असर डालने के अवसर के रूप में देख रहा है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ वर्षों में अपनी राजनीतिक परिपक्वता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं से संवाद हो या नीतीश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना। राजद के पास एक ठोस सामाजिक आधार है लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों और शासन की यादें आज भी मतदाताओं के दिमाग में ताजा हैं। कांग्रेस, वामदलों और अन्य सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर संभावित खींचतान भी गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाती है, फिर भी तेजस्वी का युवा जोश और उनके प्रचार की डिजिटल समझबूझ उन्हें पहले से अलग बनाती है। 'इंडिया' गठबंधन यह भलीभांति जानता है कि अगर बिहार में उसकी पकड़ मजबूत होती है तो यह 2029 के लोकसभा समीकरणों में एक नई ऊर्जा भर सकता है। एनडीए का चेहरा इस बार भी नीतीश कुमार ही हैं, जिनका राजनीतिक अनुभव किसी परिचय का मोहताज नहीं। वे सात बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं लेकिन अब जनता उनसे बदलाव की बजाय जवाब चाहती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है साफ छवि और साझा सामाजिक आधार। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पिछले कुछ सालों में उनके राजनीतिक पलटवारों, कभी महागठबंधन में, कभी एनडीए में आने-जाने ने उनकी विश्वसनीयता को काफी कमजोर किया है। भाजपा, जो एनडीए की दूसरी बड़ी ताकत है, नीतीश के साथ रहते हुए भी अपने संगठन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसे यह अंदाजा है कि बिहार में अगर उसे भविष्य में स्वतंत्र रूप से मजबूत होना है तो नीतीश के बाद का दौर भी ध्यान में रखना होगा। यही कारण है कि भाजपा अब स्थानीय नेताओं को उभारने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे मैदान को अपने पक्ष में करने की योजना पर काम कर रही है। एनडीए का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके पास वोटों का एक स्थिर कोर आधार है और शासन की निरंतरता की छवि बनी हुई है लेकिन एंटी-इनकम्बेंसी, बेरोजगारी और ग्रामीण ढांचों में ठहराव जैसे मुद्दे उनके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। बिहार के इस राजनीतिक त्रिकोण में सबसे दिलचस्प और नया पैदा हुआ कारक हैं प्रशांत किशोर (पीके)। उन्होंने रणनीतिकार से जननेता बनने की जो यात्रा शुरू की वह अब निर्णायक दौर में पहुंची है। उनका जन सुराज अभियान पिछले दो वर्षों से गांव-गांव में सक्रिय रहा है। वे न तो स्वयं को किसी पारंपरिक पार्टी की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं और न किसी गठबंधन का हिस्सा हैं। उनका संदेश सीधा है। »सिस्टम को बदलने के लिए राजनीति में साफ और नई सोच लानी होगी। प्रशांत किशोर का यह प्रयोग बिहार की राजनीति की जमीनी सच्चाई को चुनौती देता है। वे युवाओं और शिक्षित तबके में धीरे-धीरे एक विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि वे बड़े पैमाने पर सीटें जीतेंगे लेकिन उनका प्रभाव दो स्तरों पर होगा। वोट कटवा असर- कई क्षेत्रों में वे परंपरागत दलों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। विचारधारात्मक बदलाव- उनकी राजनीति भ्रष्टाचार विरोधी और विकास-केंद्रित विमर्श को चुनावी बहस के केंद्र में ला रही है, अगर उनका अभियान थोड़ा भी जनसमर्थन जुटाने में सफल रहता है तो यह बिहार में तीसरी शक्ति के उदय की भूमिका लिख सकता है। गौरतलब है कि बिहार की राजनीति बिना जातीय समीकरणों के समझी ही नहीं जा सकती। यादव, कुशवाहा, भूमिहार, राजपूत और मुसलमानों के बीच सामंजस्य और टकराव हमेशा परिणामों को प्रभावित करते हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक नया सामाजिक तबका, युवा और प्रवासी मजदूर वर्ग, निर्णायक बनकर उभर रहा है। प्रशासन, कृषि संकट, रोजगार और शिक्षा की स्थिति इस बार मुख्य मुद्दे होंगे। डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्मों के उदय ने इस बार चुनावी प्रचार के तरीके को भी बदल दिया है। अब गांवों तक व्हाट्सऐप समूह और सोशल अभियानों के माध्यम से राजनीतिक विमर्श पहुंच रहा है और यहां पर प्रशांत किशोर जैसे नेताओं की रणनीतिक क्षमता का उन्हें फायदा हो सकता है। इस चुनाव की सबसे बड़ी बहस विकास बनाम विश्वसनीयता की होगी। नीतीश कुमार कहेंगे कि उन्होंने राज्य को बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार दिया, जबकि विरोधी पक्ष यह पूछेगा कि इतने वर्षों में युवाओं के लिए अवसर क्यों नहीं बढ़े। तेजस्वी यादव रोजगार और सामाजिक न्याय का नारा देंगे, भाजपा मोदी के नाम और केंद्रीय योजनाओं की बदौलत वोट जुटाने की कोशिश करेगी और प्रशांत किशोर नई राजनीति की बात करेंगे। नतीजतन, यह चुनाव किसी एक मुद्दे या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यह आस्था, असंतोष और आकांक्षा के मिश्रण से तय होगा। बिहार के 2025 के चुनाव इसलिए रोचक हैं क्योंकि तीन पीढ़ियां और तीन दृष्टिकोण आमने-सामने हैं। नीतीश कुमार, जिनकी राजनीति स्थिरता और अनुभवी शासन का प्रतीक है। तेजस्वी यादव, जो परिवर्तन और युवा आकांक्षाओं के वाहक हैं। प्रशांत किशोर, जो मौजूदा राजनीति को बदलने की चुनौती दे रहे हैं। यह चुनाव यह तय करेगा कि बिहार पुरानी राजनीति की सीमाओं में रहेगा या सोच के नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाएगा। चाहे परिणाम कुछ भी हो, इतना तो तय है कि इस बार बिहार का जनादेश केवल सरकार नहीं, बल्कि देश की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।

सम्पादकीय...

स्वावलंबन

पहले हिंडनबर्ग ने और अब वाशिंगटन पोस्ट ने किस पर हमला किया है? राष्ट्र सेठ पर, राष्ट्र सेठ की दौलत पर, राष्ट्र सेठ के साम्राज्य पर। हिंडनबर्ग भी विदेशी और वाशिंगटन पोस्ट भी विदेशी। और विदेशी अमेरिका का सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी, जिसने हमारे राष्ट्र सेठ के लिए घूसखोरी के मामले में समन भेजे हैं। पर अमेरिका वाले समन भेजते समय यह भूल गए कि अब भारत में मोदी जी की यानी भारत-भक्ति फर्स्ट वाली सरकार है। और वह भी छप्पन इंच की छाती वाली सरकार। समन जारी करने वाले अमेरिकी विभाग और समन का निशाना बनने वाले राष्ट्र सेठ के बीच, मोदी सरकार फौलादी दीवार बनकर खड़ी है। बाहर से कोई भी समन बल्कि कोई भी प्रहार आएगा, उसे पहले इस फौलादी दीवार से टकराना होगा। यह बीमा से भी बढ़कर बीमा का, मोदी जी की गारंटी का मामला है। बीमा की सुरक्षा में कभी कोई चूक हो भी जाए, मोदी जी की गारंटी में कभी चूक नहीं हो सकती। सेठों के लिए गारंटी में तो अपने मोदी जी, गारंटी के भी पूरा होने की गारंटी करते हैं, जैसी डबल गारंटी की बात कभी-कभी चुनाव के टैम पर पब्लिक से भी कहते हैं। और हां! इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हिंडनबर्ग ने भारत सेठ की भारतीय शेयरधारकों से ठगी का खुलासा किया था। अमेरिकी सिक्यूरिटीज कमीशन ने भारत सेठ के खिलाफ भारतीय अधिकारियों को घूस देने का मामला बनाया है। वाशिंगटन पोस्ट ने, भारतीय जीवन बीमा निगम के 32 हजार करोड़ रुपये से, भारत सेठ की अवैध तरीके से मदद किए जाने का और वह भी मोदी सरकार के कहने पर मदद किये जाने का भंडा फोड़ किया है। भारत में हुआ तो क्या हुआ, जुर्म भारत वालों के खिलाफ हुआ तो क्या हुआ, नुकसान भारत का हुआ तो क्या हुआ? उंगली उठाने वाले तो विदेशी हैं। जुर्म करने वाला, जुर्म की मार खाने वाला, जुर्म कराने वाला, सब स्वदेशी हैं, जबकि सवाल उठाने विदेशी। इक्का-दुक्का देसी भी सवाल उठा रहे होंगे, पर विदेशियों के सवाल उठाने के बाद, विदेशियों की नकल पर। विदेशियों की नकल करने वालों का भारतीय होना भी कोई भारतीय होना है, लल्लू! अमृत काल में मोदी जी भारत को ऐसे नकली भारतीयों से ही तो मुक्त करा रहे हैं। यानी यह सिर्फ भारत सेठ की रक्षा की नहीं, स्वदेशी की रक्षा की लड़ाई है और वह भी रूसी तेल खरीदें कि नहीं खरीदें टाइप की छोटी-मोटी नहीं, बड़ी वाली लड़ाई। एक महाकाव्यात्मक लड़ाई। स्वदेशी की रक्षा की इससे बड़ी लड़ाई क्या होगी? और अब कोई कुछ भी कहे, बात कुछ भी हो, हम तो स्वदेशी की रक्षा करने वालों के साथ हैं, और आप। और ये वाशिंगटन पोस्ट वालों ने ऐसा क्या नया भंडाफोड़ कर दिया है, जिसका अमेरिका से लेकर भारत तक, सभी मोदी विरोधी शोर मचा रहे हैं? भारत सेठ की कंपनियों की मुश्किल के वक्त में मदद करने के लिए जिस एलआईसी के 32 हजार करोड़ रुपये लगाने के भंडाफोड़ की बातें की जा रही हैं, वह किस की है? भारत की। एलआईसी में लगा पैसा किस का है भारत के लोगों का! एलआईसी का नफा-नुकसान किस का है, भारत के लोगों का! जिस भारत सेठ की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सौ टंच भारतीय है, यह तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। और रही बात मोदी सरकार की, जिस पर एक ही समूह को इस तरह अनुचित फायदा पहुंचवाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, उसका तो खुद ही सबकी भारतीयता नापने और सब को पर्याप्त भारतीय होने न होने के सर्टिफिकेट बांटने का स्पेशलाइजेशन है। उसकी भारतीयता पर सवाल उठाने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ और अगर पैदा हो भी गया तो धरती के जेल वाले हिस्से में ही पाया जाएगा यानी सवाल उठाने लायक ही नहीं रह जाएगा। जेल में सवाल उठाया, किसने सुना? जब यह भारतीयों द्वारा, भारतीयों को और भारतीयों के हिस्से से फायदा पहुंचाने का मामला है, तो इसमें अमेरिकियों को इतनी ताक-झांक करने की क्या जरूरत है? ये हमारे घर के अंदर की बात। दूर हटो, दूर हटो ए दुनिया वालो, ये मामला हमारा है। और सबसे बड़ी बात ये एलआईसी का राष्ट्र सेठ की या किसी की भी मदद करना, भला जुर्म कैसे हो गया? एलआईसी का तो काम ही इंश्योरेंस यानी भरोसा देने का है। और इंश्योरेंस वाला भरोसा तो होता ही इसलिए है कि वक्त, जरूरत पर काम आए। राष्ट्र सेठ का मुश्किल टैम था। अमेरिका वालों ने समन जारी कर दिए। भारत में घूसखोरी हुई, उसके लिए भाई लोगों ने अमेरिका में मामले-मुकदमे शुरू कर दिए? पर उसका भी क्या रोना रोएं। अमेरिकियों की दूसरों के फटे में पांव फंसाने की बुरी आदत है। खुद इनके हिसाब से घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस दिलाने वाला, सब भारत में थे बल्कि सर्टिफाइड भारतीय थे, फिर भी मामला-मुकदमा अमेरिका में। क्या यह भारत के साथ खुल्लम खुल्ला अन्याय नहीं है? और इस अन्याय की वजह से जब हमारे राष्ट्र सेठ की तरफ से बाजार ने मुंह फेर लिया, बैंकों ने उनकी कंपनियों में पैसा लगाना बंद कर दिया, तब एलआईसी जीवन रक्षक बनकर सामने आयी। और यही तो एलआईसी का काम है। बल्कि यही तो उसका कमाई का मॉडल है। एलआईसी ने वाशिंगटन पोस्ट के जवाब में एकदम सही कहा है—हम यह नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया है, पर जो किया है, बहुत सोच-समझकर किया है? और किसी के कहने से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन से किया है। नफा हो या नुकसान हो, मेरी मर्जी! और कोई चोरी थोड़े ही है, जो हो रहा है, छाती ठोक के हो रहा है। मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि अब बस स्वावलंबन होगा। हम हर्गिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई बाहर वाला आकर, हमारे यहां हो रही ठगी, बेईमानी को, ठगी और बेईमानी कहकर भारत को बदनाम करे। रही देश वालों की बात, तो स्वावलंबन का विरोध करने की इजाजत तो उन्हें भी नहीं दी जाएगी। राष्ट्र सेठ हमारा। राष्ट्र सेठ की मदद करने वाली एलआईसी हमारी। राष्ट्र सेठ की मदद कराने वाली सरकार हमारी। इससे ज्यादा स्वावलंबन क्या होगा? और जब इतना स्वावलंबन हो रहा है, किसी को भ्रष्टाचार-व्रष्टाचार की बात करनी चाहिए क्या? बचपन में पढ़ा था, स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष! कहां कुबेर का कोष और कहां सिर्फ 32 हजार करोड़ रुपये!

क्या चमकेगी मुकेश सहनी, चिराग की किस्मत

अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है, राजनीति बदमाशों की आखिरी शरणस्थली होती है। बिहार में इस बार राजनीति बॉलीवुड में असफल उम्मीदवारों के लिए एक लाभदायक शरणस्थली साबित हो रही है। मौजूदा विधानसभा चुनावों में दो लोग हलचल मचा रहे हैं, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान। दोनों की बड़ी महत्वाकांक्षाएं है और चुनाव परिणाम आने पर वे किंगमेकर साबित हो सकते हैं। साहनी 19 साल की उम्र में बड़े सपने लेकर मुंबई चले गए थे। चिराग पासवान के उलट, जिन्होंने अपने अभिनय से ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, सहनी को एक सेट डिजाइनिंग टीम में नौकरी मिल गई। इस नौकरी ने उन्हें कई मुकाम दिलाए। उन्होंने शाहरुख खान की देवदास और सलमान खान की बजरंगी भाईजान के सेट डिजाइन किए, हालांकि, बॉलीवुड में काम करना उनके लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहा और सहनी शक्तिशाली जाति कार्ड के साथ राजनीति में हाथ आजमाने के लिए बिहार वापस आ गए। सहनी मल्लाह जाति से आते हैं, जो बिहार में एक छोटा लेकिन प्रभावशाली समुदाय है। अपनी जातिगत पहचान का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए सहनी ने राजद के तेजस्वी यादव को इस चुनाव में विपक्षी महागठबंधन की ओर से उन्हें उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए राजी कर लिया। चिराग पासवान अभी भी बिहार में अपनी बड़ी सफलता का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें कंगना रनौत के साथ -मिले ना मिले हम- फिल्म में मुख्य भूमिका मिली थी। फिल्म फ्लॉप रही पर कंगना आगे चलकर स्टार बन गईं। दुर्भाग्य से पासवान सफल नहीं हो पाए। प्रमुख दलित नेता रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते, राजनीति उनकी शरणस्थली बन गई। पासवान एक दलित समुदाय से हैं जिनका बिहार के कुछ हिस्सों में प्रभाव है। चिराग ने अपनी किस्मत एनडीए से जोड़ ली और आज मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। हालांकि, उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य रखा है और विधानसभा चुनाव लड़कर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सीजेआई के लिए रिजर्व बंगले ने खो दी अपील - भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए आरक्षित प्रतिष्ठित लुटियंस बंगले ने अपनी अपील खो दी है, क्योंकि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने निर्धारित समय से अधिक समय तक वहां रहकर इसे विवाद में घसीट लिया था। यह दिलचस्प है कि चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी संजीव खन्ना के साथ ही वर्तमान सीजेआई बीआर गवई ने उस घर में जाने से इनकार कर दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख का आधिकारिक निवास माना जाता है। अब ऐसा लग रहा है कि गवई के संभावित उत्तराधिकारी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी अपने मौजूदा बंगले में ही रहना चाहते हैं, और उनके बाद आने वाले मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति नागरत्ना के भी आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश आवास में जाने की संभावना कम ही है। न्यायमूर्ति नागरत्ना देश के सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होंगी, हालांकि, मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा, केवल एक महीना होगा। उधर, कई महीनों से खाली पड़े मुख्य न्यायाधीश के बंगले को लेकर शहर में सभी सरकारी आवासों का प्रभार संभालने वाला शहरी विकास मंत्रालय अब इस उलझन में है कि इसका क्या किया जाए एक सुझाव यह है कि इसे सामान्य आवास पूल में स्थानांतरित कर दिया जाए और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाए। एक अन्य सुझाव यह है कि इसे मुख्य न्यायाधीश के आधिकारिक आवास के रूप में रखा जाए और आशा की जाए कि नागरत्ना के उत्तराधिकारी, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ इसमें रहने के लिए सहमत हो जाएंगे। कर्नाटक में यतींद्र की टिप्पणियों से हलचल : कर्नाटक में अगले महीने मुख्यमंत्री बदलने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इस चर्चा की शुरुआत किसी और ने नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अपने बेटे यतींद्र ने की है। उन्होंने हाल ही में एक दिलचस्प बयान दिया कि उनके पिता अपने करियर के -अंतिम चरण- में हैं। क्या उनका आशय यह था कि सिद्धारमैया का करियर जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन यतींद्र ने और भी शरारत की। उन्होंने सतीश जरकीहोली का नाम एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में सुझाया। यतींद्र ने कहा कि जरकीहोली उनके पिता की प्रगतिशील विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। कर्नाटक में कांग्रेसी हलकों में उनकी टिप्पणियों को लेकर उत्सुकता है। यह व्यापक रूप से माना जा रहा है कि अगर सिद्धारमैया पद छोड़ते हैं, तो उनके बाद उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एक तथाकथित रोटेशनल समझौते के तहत पदभार संभालेंगे।

पीओके में दमन चक्र

कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह की हरकतें करता रहता है उनसे यह इस इलाके की हकीकत नहीं बदल सकता क्योंकि दुनिया जानती है कि इस रियासत का भारतीय संघ में विलय 26 अक्तूबर 1947 को उसी प्रकार हुआ था जिस प्रकार अन्य भारतीय रजवाड़ों का। जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने अपनी पूरी रियासत का विलय भारतीय संघ में करते वक्त साफ कर दिया था कि 26 अक्तूबर 1947 से पहले इस रियासत के स्वतन्त्र रहते जो भी समझौते अन्य किसी देश से थे उनकी हैसियत भारतीय संघ में विलय होने के बाद बदल चुकी थी और भारत की तत्कालीन संघीय सरकार पिछले किसी समझौते से नहीं बन्धी थी। अगस्त 1947 में महाराजा हरिसिंह ने पाकिस्तान के साथ यथा स्थिति (स्टैंड स्टिल) समझौता किया था जिस पर पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिये थे। महाराजा ऐसा ही समझौता भारत से भी करना चाहते थे मगर भारत ने इस पर दस्तखत नहीं किये थे। महाराजा को गलतफहमी थी कि पाकिस्तान उनकी रियासत की संप्रभुता का सम्मान करेगा मगर उसने ऐसा नहीं किया और सितम्बर महीने से ही कश्मीर में अपने फौजियों को कबायलियों के भेष में कश्मीर भेजना शुरू कर दिया और अक्तूबर महीने में बाकायदा आक्रमण शुरू कर दिया। जिस पर महाराजा ने भारत की मदद मांगी और अपनी रियासत का भारतीय संघ में विलय कर दिया। विलय होने के बाद पूरी रियासत भारतीय संघ का अविभाज्य हिस्सा उसी प्रकार बन चुकी थी जिस प्रकार मैसूर या अन्य कोई भारतीय रियासत। मैसूर रियासत का विलय भी भारतीय संघ में 14 अगस्त 1947 को हुआ था। विलय की शर्तों के अनुसार मैसूर के महाराजा को राजप्रमुख बना दिया गया था। ऐसा ही अन्य बड़ी देशी रियासतों के विलय के बाद भी किया गया था। ठीक यही जम्मू-कश्मीर के विलय के बाद भी हुआ और इस रियासत के राजकुमार कर्ण सिंह को सदर-ए-रियासत बना दिया गया था। अतः यह विलय पूरी तरह स्थायी था और किसी प्रकार की अन्य शर्त से बंधा हुआ नहीं था। बाद में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष धारा या अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया जिसे 370 कहा जाता था। मगर विगत 5 अगस्त 2019 को इसे भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसका प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने वक्ती अस्थायी तौर पर किया था। पाकिस्तान इस प्रावधान के समाप्त किये जाने के बाद से ही विश्व के मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश करता रहता है और अनर्गल प्रलाप में व्यस्त रहता है तथा सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है, जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य का एक तिहाई हिस्सा इसके कब्जे में 1948 से ही पड़ा हुआ है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताकर दुनिया को धोखे में रखना चाहता है और यहां के लोगों पर जुल्म ढहाता रहता है। पाकिस्तान ने कश्मीर के इस इलाके की जनसांख्यिकी बदलने तक की भरपूर कोशिश की है और पाकिस्तान के अन्य इलाकों से लोग ला-लाकर यहां बसाये हैं और उन्हें विशेषाधिकारों से लैस किया है। इसके खिलाफ मुकामी या स्थानीय लोग आवाज उठाते हैं तो उन पर गोलियां व लाठियां बरसाई जाती हैं।

भारत की बहुभाषिक डिजिटल क्रांति-भाषाई डिजिटल पुनर्जागरण- मातृभाषा में डिजिटल अधिकार-तकनीक, संस्कृति और समावेशन का नया युग

वैश्विक स्तरपर भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे युवा जनसंख्या और सबसे विविध भाषाई पहचान वाला देश है, जहाँ भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और पहचान की जीवंत धरोहर है। भारतीयों के लिए भाषा आत्मा की आवाज़ है। भारत का भाषाई परिदृश्य दुनियाँ में सबसे अनूठा है, जहाँ 22 अनुसूचित भाषाएँ, 122 प्रमुख भाषाएं और 19,500 + बोलियाँ बोली जाती है। इतने विशाल भाषाई विस्तार के साथ डिजिटल परिवर्तन को समावेशी बनाना एक बड़ी चुनौती और साथ ही एक विशाल अवसर है।भाषा केवल संचार नहीं, एक सभ्यता की आत्मा है,भाषा किसी भी मानव समाज के भावनात्मक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की वाहक होती है। भाषा के माध्यम से ज्ञान पीढ़ियों तक प्रवाहित होता है। यह व्यक्ति को जड़ों से जुड़ा बनाती है, उसकी पहचान स्थापित करती है और उसे समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है। किसी भी देश के डिजिटल विकास का मूल्यांकन तभी सार्थक है जब उसकी तकनीक किसी व्यक्ति की मातृभाषा को सम्मान दे। यदि व्यक्ति अपने अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर उसी भाषा में समझ पाए जिसे उसने बचपन से सीखा है, तब ही तकनीक वास्तविक समावेशन की शक्ति बनती है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि आज 'भाषा- टीकाकरण' और 'भाषा-समावेशन' का युग है और भारत अपने विशाल भाषाई समृद्धि को केवल चुनौती नहीं मान रहा, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाकर आगे बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष-दशक में यह दृष्टि फलीभूत होगी,और भारत का प्रत्येक नागरिकअपनी मातृभाषा में,अपनी बोली में,तकनीक, नवाचार और सामाजिक- उन्नति का हिस्सा बनेगा।आज भारत तेजी से डिजिटल सुपरपावर बनने की ओर अग्रसर है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सरकार की डिजिटल इंडिया नीति ने एक नए युग की शुरुआत की है,जहाँ हर नागरिक को अपनी मातृभाषा में डिजिटल अधिकार, सेवाओं तक पहुँच और सूचना की स्वतंत्रता मिले। यही भारत के भाषाई डिजिटल पुनर्जागरण की असली नींव है।भारत का भाषाई परिदृश्य वास्तव में विश्व में अद्वितीय है। भारत में केवल 22 अनुसूचित भाषाएँ ही नहीं रह गई, बल्कि सैकड़ों जनजातीय तथा क्षेत्रीय बोलियाँ पूरे भौगोलिक विस्तार में विद्यमान है। यह विविधता केवल संख्या-का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक,भाषाई एवं राजनैतिक जटिलताओं का द्योतक है। उदाहरणतः संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित किया गया है,जो यह संकेत देती है कि इनमें सरकारी, शैक्षिक, न्याय- प्रक्रिया और सार्वजनिक संवाद की दृष्टि से विशेष संवैधानिक मान्यता है। इसके अतिरिक्त,भारत के प्रत्येक राज्य एवं क्षेत्र में स्थानीय-भाषा और बोलियों का अपना स्थान है, सौ-सौ वर्षों से चली आ रही संवाद-परंपराएँ है, और ये बोलियाँ सिर्फ बोली के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत तथा अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार भारत में भाषा का प्रश्न केवल भाषाई संरचना तक सीमित नहीं है यह क्षेत्रीय-तक निजी-तक पहचान, सामाजिक-तक राजनैतिक संदर्भ, और तकनीकी-तक डिजिटल समावेशन का विषय भी है। साथियों बात अगर हम इस विशेषता के कारण जब हम डिजिटल परिवर्तन की दिशा में देखते हैं तो,भारत की बहुभाषिक डिजिटल क्रांति यानी संवाद, सूचना ,संचार, इंटरफेस तकनीकें, इंटरनेट-आधारित सेवाएँ स्मार्टफोन -एप्लिकेशन-सिस्टम आदि,तो दूसरे बिंदु के रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसे-जैसे डिजिटल बदलाव तेज हो रहा है, इस भाषाई विविधता को डिजिटल बुनियादी ढाँचे में समाहित करना बेहद जरूरी हो गया है। तकनीक अब केवल संचार का माध्यम नहीं रह गई है,यह आज समावेशन की रीढ़ बन चुकी है।यदि केवल अंग्रेजी या मात्र एक-दो प्रमुख भाषाएँ तकनीक-उपकरणों, एप्लिकेशन इंटरफेस,सोशल-मीडियाप्लेटफार्म, सरकारी-डिजिटल सेवाओं में प्राथमिक हो, तो भाषाई बहुलता वाले देश में यह एक बड़ा समावेशन-विरोध पैदा कर सकती है, अर्थात- भाषाई रूप से पिछड़े समुदाय, बोलियों- भाषाओं में रहने वाले नागरिक, स्थानीय-भाषा बोलने वाले उपयोगकर्ता डिजिटल विभाजन के शिकार हो सकते है। इसलिए, यह आवश्यक है कि डिजिटल परिवर्तन-प्रक्रिया में इन भाषाओं और बोलियों को तुरंत, आत्मसात और प्रभावी रूप से शामिल किया जाए। जब मोबाइल-इंटरनेट पहुँच, स्मार्टफोन-यूजरसंख्या, सरकारी-ऑनलाइन सेवाएँ और निजी-उपकरणों-एप्लिकेशनों में वृद्धि हो रही है,तब भाषा- समावेशन, हम सिर्फ सामाजिक- सद्भावना की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक-सांस्कृतिक एवं डिजिटल- सशक्तिकरण की दृष्टि से भी अनिवार्य बन गयी है। इसके परिणामस्वरूप यह माना जाना चाहिए कि भाषा- उपकरणों स्थानीय-भाषा इंटरफेस, वॉइस-आधारित इंटरैक्शन, रीयल-टाइम अनुवाद, ध्वनि-सक्षम माध्यमों के विकास से ही डिजिटल अर्थव्यवस्था का वास्तविक लाभ सभी नागरिकों तक पहुँच सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा में नहीं समझ पाता, तो वह उस डिजिटल प्लेटफार्म की पूरी क्षमता से लाभ नहीं उठा पाएगा और यहीं पर टूटा हुआ समावेशन और वृद्धि-विरोधन अंतर बन जाता है। साथियों बात अगर हम भारत सरकार तथा तकनीकी क्षेत्र ने इस समझ के आधार पर सक्रिय कदम उठाना शुरू कर दिया है इसको समझने की करें तो, एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), एनएलपी (प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण), मशीन लर्निंग तथा वाक-पहचान जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करके बुद्धिमान और मापयोग्य भाषा समाधान विकसित करना। उदाहरण के रूप में, राज्य-स्तर तथा केंद्र-स्तर पर अनेक पहलों ने लोकसेवा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य एवं वित्तीय सेवाओं में भाषा- समर्थन पर ध्यान दिया है, जो एक उल्लेखनीय पहल है भाषिणी-यह एक राष्ट्रीय भाषा अनुवादमिशन-आधारित प्लेटफार्म है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद, मल्टीलिंगुअल मॉडल और वह-इंटरफेस बना रहा है। इसके अलावा अनुसंधान-कागजात ने दिखाया है कि भारतीय-भाषाओं हेतु विशिष्ट मल्टीलिंगुअल मॉडल जैसे मुरिल तैयार किए गए है, जिनका उद्देश्य है कि भारतीय भाषाओं के लिए प्रदत्त डेटा-सेट्स तथा रिजल्ट-मॉडल अंग्रेजी-केन्द्रीय मॉडल्स की तुलना में बेहतर हों।

इन तकनीकी पहलों का उद्देश्य हैनिर्बाध संचार, रीयल-टाइम अनुवाद, ध्वनि-सक्षम इंटरफेस और स्थानीयकृत सामग्री वितरण को सक्षम करके डिजिटल सेवाओं तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना।अर्थात- न केवल अंग्रेजी-माध्यम उपयोग कर्ताओं को बल्कि मातृभाषा-उपयोगकर्ताओं को भी-साथ लाना।भाषा-विविधता का सम्मान करने वाले एक मजबूत तकनीकी व्यवस्था-तंत्र के निर्माण करते भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ हर नागरिक, अपनी मातृभाषा के सहयोग से,डिजिटल अर्थव्यवस्था और शासन का हिस्सा बन सकेगा। भाषा-समर्थित सेवाएँ, इंटरफेस- स्थापनाएँ, स्थानीयकृत कंटेंट, वॉइस- आधारित इंटरैक्शन जैसे सशक्त उपकरण आज वास्तविक हो रहे है। इससे वे लोग भी डिजिटल अर्थव्यवस्था ई-गवर्नेंस, औद्योगिक-इनोवेशन -सेवाएँ आदि का लाभ उठा सकेंगे जिनका पहला भाषा- सक्षम उनकी मातृभाषा है। इससे एक तथ्य से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भाषा-दोष डिजिटल-दोष में नहीं बदल जाए। जब प्रत्येक राज्य- जनसंख्या-भाषा को मान्यता मिलती है, तो यह न सिर्फ तकनीकी समावेशन का प्रश्न है, बल्कि वह सामाजिक न्याय-प्रश्न भी है, जिससे भाषा-अधिकार एवं डिजिटल-अधिकार एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस दृष्टि से, भाषा केवल एक माध्यम नहीं रही बल्कि एक अधिकार-आधार भी बन चुकी है, और इसके पालन-संबल को तकनीकी सन्दर्भ में सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अब सरकारों,उद्योगों और शोध- समुदायों पर है। साथियों बात कर हम भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है,यह किसी सभ्यता की आत्मा है, इसकी संस्कृति है, इसकी विरासत है, इसको समझने की करें तो, जब हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करते है,अपने रीति-रिवाजों, लोक-कथाओं, गीत-साहित्य, तकनीकी व संवाद-परिस्थितियों में उसे प्रयोग करते है,तो हम एक सम्पूर्ण सामाजिक-मानवीय तंत्र को सक्रिय करते है।भाषा-विविधता का सम्मान करना हमारे लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक भाषा एक विशेष दुनियाँ समाहित करती है,उसमें स्थानीय अनुभव, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और संवाद-शैली होती है। यदि डिजिटल जमाना ऐसी भाषा- विविधता को नजर अंदाज करे, यदि टेक्नोलॉजी केवल कुछ प्रमुख भाषाओं तक सीमित रहे, तो न केवल भाषा-वंचित समुदाय पीछे रह जाएंगे बल्कि उनके संवाद-विश्व,उनकी सामाजिक- पहचान और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जोखिम होगा।इसलिए, भाषा-समर्थन सिर्फ एकतकनीकी सुविधा नहीं है, यह सभ्यता-रक्षा, संस्कृति- संरक्षण और मानव-समानता का सवाल भी है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत ने एक दुर्लभ अवसर सामना किया है,जहाँ एक ओर उसकी भाषाई विविधता बहुत बड़ी चुनौति है,लेकिन दूसरी ओर वही विविधता उसके लिए समावेशन,नवाचार और वैश्विक-तक प्रतिस्पर्धा का आधार भी बन सकती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीतमपुरा एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2017/...)

छठ महापर्व पर भाजपा सरकार ने खोले शराब के ठेके, सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए पूछे सवाल

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। छठ पर्व पर दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें खुली होने पर उन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी किया। साथ ही वीडियो में उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल पूछा। एक्स पर सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि नकली एक्यूआई, नकली यमुना और नकली सनातनी हैं। छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने सारे शराब के ठेके खोल दिए हैं। जबकि केजरीवाल सरकार में बंद रहते थे। नकली सनातन सरकार आते ही शराब के सारे ठेके खोले गए। उन्होंने आगे लिखा कि अब देखते हैं नकली सनातन सोशल मीडिया नायक क्या करते हैं? पूर्वांचल आस्था का अपमान असली सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।

यमुना सफाई पर आप-भाजपा में तीखा टकराव

छठ पर्व से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रधानमंत्री के लिए वासुदेव घाट पर 'फिल्टर वाटर' की नकली यमुना तैयार कराई है, ताकि बिहार चुनाव से पहले स्वच्छता का झूठा प्रचार किया जा सके। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के बयान राजनीतिक हताशा का प्रतीक बताया। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 2018 से 2024 तक छठ पूजा पर रोक लगाई थी, जबकि रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ आठ महीने में यमुना घाटों को साफ किया।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने संवाददाता सम्मेलन ने कहा कि

भाजपा पूर्वांचल समाज को गुमराह करने के लिए हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने का नाटक कर रही है ताकि यमुना का प्रदूषण कम दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब झूठ पर झूठ बोलकर बिहार चुनाव के मद्देनजर छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी सेहत का पूरा ख्याल है, इसलिए उनके लिए फिल्टर वाटर का घाट बनाया गया है, लेकिन छठव्रती दूषित यमुना में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। भाजपा सरकार झाग हटाने के लिए उसी केमिकल इस्तेमाल कर रही है, जिसे पहले भाजपा नेता जहर बताते थे। उन्होंने कहा कि अगर यमुना साफ है तो भाजपा नेता मीडिया के सामने उसी पानी को पीकर दिखाएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा कि आज दिल्ली ने एक नया राजनीतिक प्रपंच देखा। विपक्ष ने सफाई पर आपत्ति की। सौरभ भारद्वाज का वीडियो हास्यास्पद था। उन्होंने खुद को मजाक का पात्र बना लिया। केजरीवाल सरकार ने 2018 से 2024 तक बिना किसी आदेश के यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगाई थी, जिससे पूर्वांचल समाज में आक्रोश फैला था। आज जब रेखा गुप्ता सरकार ने आठ महीने में घाटों की बेसिक सफाई पूरी की है, तो आप इसे सहन नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर सुरक्षा चाक-चौबंद

नई दिल्ली। छठ महापर्व के मौके पर राजधानी के वासुदेव घाट पर अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच सकते हैं। हालांकि, इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा से जब पत्रकारों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि यहां पीएम आ रहे हैं। वासुदेव घाट पर इन दिनों प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां मीडिया प्रतिनिधियों को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि, भाजपा सूत्रों का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय है, तो यह 'यमुना पुनर्जीवन' और 'छठ पर्व की स्वच्छता' दोनों को लेकर एक प्रतीकात्मक संदेश देने के उद्देश्य से होगा।

उचतम न्यायालय 'डिजिटल अरेस्ट' के सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने के पक्ष में

नई दिल्ली ।उचतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की पूरे भारत में व्यापकता को देखते हुए इनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का इच्छुक है। न्यायालय ने 'डिजिटल अरेस्ट' संबंधी मामलों में विभिन्न रायों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज प्राथमिकियों का ब्यौरा मांगा। 'डिजिटल अरेस्ट' ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जिसमें जालसाज खुद को फर्जी तरीके से किसी सरकारी एजेंसी या पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों पर कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें धमकाते हैं और गलत तरह से धन वसूली की कोशिश करते हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों पर सभी रायों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किए और धोखेबाजों द्वारा ठगी की शिकार एक बुजुर्ग महिला की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए मामलों की सुनवाई तीन नवंबर के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील पर गौर किया कि साइबर अपराध और 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों का मूल म्यांमा और थाईलैंड जैसे विदेशी स्थानों से है। साथ ही न्यायालय ने जांच एजेंसी को इन मामलों की जांच के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ''हम सीबीआई जांच की प्रगति की निगरानी करेंगे और आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।'' पीठ ने सीबीआई से पूछा कि क्या उसे 'डिजिटल अरेस्ट' के मामलों की जांच के लिए पुलिस बल से बाहर के साइबर विशेषज्ञों सहित अधिक संसाधनों की आवश्यकता है ? न्यायालय ने देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में केंद्र और सीबीआई से 17 अक्टूबर के जवाब मांगा था और कहा था कि इस तरह के अपराध न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास की नींव पर कुठाराघात हैं। शीर्ष अदालत ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे 1.05 करोड़ रुपये की उगाही की घटना का संज्ञान लिया है। उसने कहा था कि यह साधारण अपराध नहीं है जिसमें पुलिस से कह दिया जाए कि तेजी से जांच करे और मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाए बल्कि यह ऐसा मामला है जिसमें आपराधिक उपक्रम का पूरी तरह पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राय पुलिस के बीच समन्वित प्रयास जरूरी हैं।

सीजेआई पर जूता उछालने वाले वकील के खिलाफ नहीं होगी अवमानना की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मन नहीं है

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सोमवार को कहा कि वे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की कोशिश करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश खुद ही आरोपी वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अदालत में नारेबाजी करने और जूता उछालना यकीनन अदालत की अवमानना है, लेकिन ये संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वे कानून के तहत कार्रवाई करते हैं या नहीं। पीठ ने कहा कि अवमानना का नोटिस जारी करने से उस वकील को चर्चा ही मिलेगी, जिसने मुख्य न्यायाधीश की तरफ जूता उछाला। इससे घटना को बेवजह का तूल मिलेगा। पीठ ने कहा कि इस घटना को अपने आप ही खत्म होने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील राकेश किशोर के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। सर्वोच अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए अदालत दिशा-निर्देश जारी करेगी। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विभिन्न अदालतों में जूता उछालने की घटनाओं का की जानकारी देने को कहा है। इससे पहले 16 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरों की गरिमा और सत्यनिष्ठा की कीमत पर नहीं दी जा सकतीं। पीठ ने बेलगाम सोशल मीडिया के खतरे को लेकर भी आगाह किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं पैसा कमाने के धंधे से यादा कुछ नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने वाली घटना को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और घटना का महिमामंडन करने के संबंध में भी विचार करने के बाद दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई पर जूता उछालने की घटना 6 अक्तूबर को हुई थी। यह घटना उस वक्त हुई, जब सीजेआई एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे। सीजेआई की एक टिप्पणी से नाराज होकर कथित तौर पर आरोपी वकील ने इस घटना को अंजाम देने की बात कही। घटना के बाद सीजेआई ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस मामले की पूरे देश में चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर बात भी की थी।

लिव-इन पार्टनर ने किया कत्ल : अश्लील फोटो डिलीट करने को तैयार न था प्रेमी, युवती ने पूर्व आशिक संग मिल मार डाला

नई दिल्ली । उत्तरी जिला के तिमारपुर इलाके में 5 अक्तूबर की रात यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र रामकेश मीणा (32) की मौत आग लगने से नहीं हुई थी। उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को सुलझाते हुए रामकेश के साथ सहमति संबंध में रहने वाली युवती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुरादाबाद निवासी अमृता चौहान (21), सुमित कश्यप (27) और संदीप कुमार (29) के रूप में हुई है। दरअसल, रामकेश के पास अमृता के अश्लील वीडियो और फोटो एक हार्ड डिस्क में थे। बार-बार मांगने पर वह उनको नहीं दे रहा था। इसी बात पर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी सुमित के साथ मिलकर रामकेश की हत्या की साजिश रची। 5 अक्तूबर की रात को उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पेट्रोल डालकर कमरे में आग लगा दी। बाद में रसोई से एलपीजी सिलिंडर को खोलकर उसे भी आग में रख दिया गया। आग लगाने से पहले आरोपियों ने हार्ड डिस्क, ट्रॉली बैग व अन्य सामान कमरे से ले लिया। पुलिस ने इसको बरामद कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अमृता ने अपराध कबूल करते हुए घटनाक्रम की जानकारी दी। उसने बताया कि वह मृतक रामकेश मीणा के साथ मई 2025 से सहमति संबंध में रह रही थी। अश्लील फोटो और वीडियो डिलीट करने को कहा तो वह तैयार नहीं हुआ। यह बात उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप को बताई। हत्या में सुमित ने अपने दोस्त संदीप को शामिल किया। 5-6 अक्तूबर की रात तीनों ने रामकेश की गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में कमरे में पेट्रोल और शराब डालकर शव को आग के हवाले कर दिया। सुमित मुरादाबाद में गैस सिलिंडर का डिस्ट्रीब्यूटर है। उसने सिलेंडर खोलकर आग लगाई ताकि विस्फोट से मामला हादसे के जैसा लगे। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त राजा बांठिया ने बताया कि 6 अक्तूबर की रात को गांधी विहार स्थित मकान नंबर-ई-60 की चौथी मंजिल पर आग लगने की खबर मिली थी।

दिल्ली में आज सुबह फिर ठांय-ठांय : राजौरी गार्डन और अमर कॉलोनी में मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल

नई दिल्ली । राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मुठभेड़ की खबर सामने आई है। राजौरी गार्डन में दिल्ली पुलिस के साथ अपराधी के बीच गोलीबारी हुई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजौरी गार्डन इलाके में दिल्ली पुलिस और एक अपराधी के बीच संक्षिप्त गोलीबारी हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अमर कॉलोनी में पुलिस और एक वांछित अपराधी के बीच हत्या के प्रयास के मामले में संक्षिप्त गोलीबारी हुई। गोलीबारी के बाद अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने दिवाली वाले दिन तैमूर नगर में फायरिंग करने वाले आरोपी तेजस उर्फ भारत को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। दो पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं।

उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर 31 अक्टूबर को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली पुलिस को झटका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्तों का समय देने से इनकार कर दिया है। ये सभी लोग 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े बड़े मामले में आरोपी हैं। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से समय मांगा। लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजनिया की बेंच ने कहा, हमने पहले ही काफी समय दे दिया है। पिछली बार साफ कहा गया था कि 27 अक्टूबर को सुनवाई होग और मामला निपटाया जाएगा। बेल मामलों में जवाब दाखिल करने का सवाल ही नहीं उठता है।

सिब्बल और सिंघवी की दलील

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो उमर खालिद की ओर से पेश हुए उन्होंने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल से जेल में बंद हैं। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल में काफी देरी हो चुकी है इसलिए अब और देर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। अब अदालत 31 अक्टूबर को इस मामले

की सुनवाई करेगी। बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत 9 लोगों की जमानत याचिका खारिज की थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा था कि साजिश के तहत हिंसा को विरोध प्रदर्शन के नाम पर बढ़ावा देना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और वाजिब प्रतिबंधों के अधीन है। हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि बिना सीमा के विरोध की अनुमति दी जाए तो यह संवैधानिक ढांचे और कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें खालिद, इमाम और अन्य आरोपियों पर UAPA और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पुलिस का आरोप है कि ये सभी फरवरी 2020 में भड़के दंगों के मास्टरमाइंड थे, जिसमें 53 लोगों की मौत और 700 से यादा लोग घायल हुए थे।

किस बात का हो रहा था विरोध?

यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। हालांकि, आरोपियों ने सभी आरोपों से इनकार किया है और निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

दिल्ली के वासुदेव घाट पर सियासत, सौरभ भारद्वाज के आरोप पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिया जवाब

नई दिल्ली । दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई और उसके किनारे बने घाटों की सफाई और व्यवस्था पर सियासी जंग तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने यमुना किनारे वासुदेव घाट से सटे कृत्रिम घाट बनाए जाने का आरोप लगाते हुए वीडियो बयान जारी किया, तो बीजेपी ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया. बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप नेतृत्व को जनता की आस्था और स्वच्छता से आपत्ति है, जबकि 8 महीने में रेखा गुप्ता सरकार ने बेसिक सफाई कर कर यमुना के किनारे प्राकृतिक घाटों को नया जीवन दिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के मॉडल का गुणगान करती थी, लेकिन आज वही पार्टी राजनीतिक हताशा का मॉडल बनकर रह गई है. उन्होंने कहा कि दिल्ली का पूर्वांचल समाज यह देखकर हैरान है कि आखिर आप नेतृत्व को यमुना किनारे बने प्राकृतिक छठ घाटों के विकास पर इतनी आपत्ति क्यों है. वीरेंद्र सचदेवा ने सौरभ भारद्वाज के उस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने वासुदेव घाट पर किए जा रहे कार्यों को कृत्रिम बताया था. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, देश में विपक्ष को विकास के अभाव या गंदगी पर आपत्ति करते देखा है, लेकिन पहली बार कोई विपक्ष सरकार की सफाई पर नाराज है. उन्होंने कहा, सौरभ भारद्वाज ने यमुना की सफाई और स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर सवाल उठाकर खुद को हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा दिया है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के समय बिहार समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया गया. वर्ष 2018 से 2024 तक बिना किसी प्रशासनिक या न्यायिक आपत्ति के यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगाई गई थी. अब जब रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ आठ महीने में यमुना-घाटों की सफाई कर प्राकृतिक स्वरूप लौटाया, तो आम आदमी पार्टी को परेशानी होने लगी है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, किस आधार पर वर्ष 2018 से 2024 तक यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगाई गई? और यमुना घाटों की सफाई और स्वच्छ जल की व्यवस्था से आखिर आप नेतृत्व को दिक्कत क्यों है? इन दोनों सवालों के जवाब दिल्ली का बिहार समाज अब आप नेतृत्व से मांग रहा है. वहीं, पत्रकार सम्मेलन का संचालन कर रहे बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने भी आप और इसके नेता सौरभ भारद्वाज को आड़े-हाथों लिया. उन्होंने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने सुबह एक बड़े खुलासे की घोषणा की थी, जिस पर उन्होंने पहले ही व्यंग्य करते हुए पोस्ट किया था – तैयार रहिए 11.30 बजे सौरभ भारद्वाज की 'मनगढ़ंत कहानियों' की ताजा एडिशन के लिए. कपूर ने तंज कसते हुए कहा, जब सौरभ लाइव आए,

पांच हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
सात नए इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को सरकार की मंजूरी

नई दिल्ली ।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 7 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। 5,532 करोड़ निवेश से 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर बनेंगे। जानिए इस योजना से देश को कैसे मिलेगा फायदा।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सात नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि सरकार को इस योजना के तहत कुल 249 प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से प्रारंभिक चरण में 7 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड बेस, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर लैमिनेट और पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म्स (जो कैपेसिटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होती है) के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने बताया कि इन सात प्रोजेक्ट्स में कुल 5,532 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इससे लगभग 5,195 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 1.15 लाख करोड़ मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जो देश में बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षमताओं का संकेत है।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम

सरकार की यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को और बल देगी। इस योजना के तहत देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाने, आयात पर निर्भरता घटाने, और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत तेजी से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हब बनता जा रहा है। मोबाइल फोन से लेकर सेमीकंडक्टर और अब कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाई जाए।

कैपिटल इंक्रिपमेंट्स के लिए आवेदन की विंडो अभी भी खुली

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के पहले चरण की आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर को समाप्त हो चुकी है, जबकि कैपिटल इंक्रिपमेंट्स के लिए आवेदन की विंडो अभी खुली हुई है। सरकार का कहना है कि इस स्कीम के दूसरे चरण में और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में देश की भागीदारी और भी मजबूत होगी।

तेजी से बढ़ रहा भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर

बीते दस वर्षों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करीब चार गुना बढ़ चुका है। यह 2014 के 2.4 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में 9.8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग अकेले 4.4 लाख करोड़ के स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ का निर्यात शामिल है। सरकार का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ मोबाइल, बल्कि चिप्स, कंपोनेंट्स और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन में भी दुनिया का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।

डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, छठी मैया के जयघोष से गूंज उठा पूरा देश, हर घाट पर उमड़ी आस्था की लहर

नई दिल्ली ।

देशभर में आज लोक आस्था का महापर्व छठ अपने चरम पर रहा। जब डूबते सूरज को अर्घ्य देने का क्षण आया, तब हर घाट, हर जलाशय, हर छत और हर बालकनी से भक्ति की गूंज उठी– 'छठी मइया के जयकारे लगल बाज यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय था। सर पर टोकरी लिए श्रद्धालु पुरुष, सिर पर चुनरी ओढ़े गीत गातीं महिलाएं और उनके संग चलतीं बच्चों की टोलीं, पूरा वातावरण मानो एक जीवंत लोककथा बन गया था। सूर्यदेव के समक्ष हाथ जोड़े लोगों में भक्ति की आभा झलक रही थी और हर श्रद्धालु के चेहरे पर 'आस्था का तेज' स्पष्ट दिख रहा था। छठ व्रतियों ने जब डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो जल ही नहीं, आत्मा भी सूर्य में विलीन हो रही हो। व्रतियों के होठों पर लोकगीत थे और वातावरण में धूप, गन्ना, ठेकुआ और लाल सूरज की आभा एक साथ घुलमिलकर संस्कार, श्रद्धा और संस्कृति का संगम रच रही थी। देश के हर हिस्से में, चाहे वह दिल्ली-नोएडा का आधुनिक अपार्टमेंट हो या पटना का गंगाघाट–छठ की भव्यता का एक ही रंग था- समर्पण। दिल्ली-एनसीआर में जब श्रद्धालुओं ने एक स्वर में सूर्यदेव को नमन किया, तो लगा कि महानगरों की भागदौड़ के बीच भी भारतीय परंपरा का दीपक अभी जल रहा है। वहीं सभ सरकारों और सामाजिक संगठनों की ओर से की गई व्यवस्थाओं ने इस पर्व को और भी सुव्यवस्थित बना दिया। हर घाट पर सुरक्षा, स्वच्छता और सेवा के भाव का सुंदर समन्वय देखने को मिला जिससे श्रद्धालु खुश नजर आये। उधर, बिहार में यह पर्व अपने पारंपरिक वैभव के साथ-साथ इस बार राजनीतिक चमक से भी सराबोर रहा। चुनावी मौसम में भी छठ का सूर्य किसी दल का नहीं, बल्कि जनभावना का प्रतीक बन गया। गंगा घाटों पर उमड़ी लाखों की भीड़ ने एक स्वर में कहा– सूर्य हैं साक्षी हैं, श्रद्धा है पहचान है। इसी बीच एक अनोखा दृश्य राजनीति के आकाश में भी उभरा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। वहां उन्होंने छठ पर्व के 'खरना' का प्रसाद ग्रहण किया। यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि आस्था और राजनीति के संगम का प्रतीक था– जहां धर्म ने राजनीति को भी विनम्र बना दिया। हम आपको बता दें कि मंगलवार सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, तब यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न होगा। लेकिन यह समाप्ति नहीं, बल्कि नवआरंभ होगी– क्योंकि छठ हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन में अंधकार आए, परंतु सूर्य फिर उगता है, और हर बार हमारे भीतर की आस्था उसे देखने को तैयार रहती है।

महागठबंधन आज करेगा मेनिफेस्टो जारी, प्रियंका गांधी की भी रैली

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज मंगलवार को छठ खत्म होते ही इसमें तेजी आएगी। प्रियंका गांधी मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही हैं। आज वो बेगूसराय आएंगी, जिले के बलिया में उनकी सभा होगी। वहीं राहुल गांधी के 29 अक्टूबर को आने की खबर है। बिहार चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन का घोषणापत्र तैयार हो गया है। पटना में आज (मंगलवार) शाम 4 बजे इसे जारी किया जाएगा, लेकिन इस मौके पर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे। इधर, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। तेजस्वी यादव कौन सी दुनिया में हैं। तिवारी ने कहा- तेजस्वी ने लड़ाई-झगड़ा करके अपना नाम सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करवाया है। हमारे गठबंधन में पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा तय है। 18वीं बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों और दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इन दोनों चरणों में कुल 2616 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1085 प्रत्याशी यानी करीब 41% पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं, बल्कि अपने बल पर चलती है - अमित शाह

मुंबई ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा को बैसाखियों की जरूरत नहीं है और वह अपने बल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में जिम्मा का सफाया सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने हमेशा संगठन की अवधारणा के आधार पर अपनी पार्टी के कामकाज को स्वीकार किया है। हमने हमेशा सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीतियां बनाई है। हमने देश और इसके लोगों के सर्वोत्तम हित में सबसे कठिन लड़ाई लड़ी है। दक्षिण मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के पास महाराष्ट्र भाजपा के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, हमने साबित कर दिया है कि परिवार द्वारा संचालित पार्टियों की राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। काम की राजनीति ही देश को आगे ले जाएगी। मोदी जी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है।

एक साधारण चायवाले के घर में जन्मा एक बच्चा अपने समर्पण, त्याग और कड़ी मेहनत से भारत का प्रधानमंत्री बना।

शाह ने निकाय चुनावों में जीत दिलाने की अपील की

अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा बैसाखियों पर नहीं, बल्कि अपने बल पर चलती है। केंद्र और राय में भाजपा की डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भी जीतने चाहिए। इतनी मेहनत करो कि विपक्ष का सफाया हो जाए। वे दूरबीन से भी नजर न आएं। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जो पार्टी अपने कामकाज में लोकतंत्र को कायम नहीं रख सकती, वह देश के लोकतंत्र की रक्षा कभी नहीं कर सकती। यह सभी वंशवादी पार्टियों के लिए एक कड़ा संदेश है। शाह ने कहा कि भाजपा के लिए पार्टी कार्यालय एक मंदिर की तरह है। उन्होंने कहा, यहीं से पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों की कल्पना की जाती है और यह पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण स्थल है। शाह ने कहा कि जनसंघ के दिनों से ही विचारधारा से प्रेरित राजनीति और जन कल्याण भाजपा की पहचान रही है। 1980 में जब भाजपा का गठन हुआ था, तब से 18 वर्षों तक देश का नेतृत्व भाजपा नेताओं ने किया है और यह गर्व की बात है। शाह ने पार्टी की सफलता का श्रेय नेताओं और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, त्याग और प्रतिबद्धता को दिया। उन्होंने कहा, उनके द्वारा बोए गए बीजों की वजह से ही भाजपा एक वटवृक्ष बन पाई है।

भाजपा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती है

उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चलती है और मेहनती और प्रदर्शन-उन्मुख कार्यकर्ता पार्टी पदानुक्रम में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं बूथ अध्यक्ष था और स्थानीय अध्यक्ष बना, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक गरीब परिवार से हैं, अपनी प्रतिबद्धता और त्याग के कारण तीन बार देश का नेतृत्व कर पाए। शाह ने 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैले नए राय भाजपा कार्यालय पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें एक पुस्तकालय, बैठक कक्ष, सम्मेलन कक्ष, 400 सीटों वाला एक सभागार और राय भाजपा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के कार्यालय शामिल हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को याद रखेगा कि वे पार्टी की बदौलत इस पद पर पहुंचे हैं। शाह ने कहा कि पार्किंग के लिए बहु-स्तरीय बेसमेंट होगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा है कि मेरे जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं के रहने के लिए तीन-चार कमरे होने चाहिए। विपक्ष ने राय भाजपा के नए कार्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाए हैं। शाह को लिखे एक पत्र में, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने भूमि अधिग्रहण पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि यह भूमि आवासीय उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी।

रूस में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट

मॉस्को । रूस ने 21 अक्टूबर को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पहली क्रूज का परीक्षण किया। रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक-9 एम739 का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैंडिवो कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले कई एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार भी बन सकता है, लेकिन यह हकीकत बन चुका है। रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। इस टेस्ट में बुरेवेस्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी।

अनुसंधान और विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता कोई भी देश, रक्षा विनिर्माताओं से बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को भारतीय रक्षा विनिर्माता सोसायटी (एसआईडीएम) के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह सच्चाई है कि कोई भी देश अनुसंधान और विकास के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या दक्षिण कोरिया...जो भी देश आगे गए हैं, वो अनुसंधान और विकास की वजह से ही गए हैं उन्होंने आगे कहा, सीखने के लिए तो हमें कहीं से भी किसी से भी सीखना चाहिए। हम तो आनी भद्रा जतवो यन्तु विश्वत की सोच को मानने वाले लोग है। दुनिया में अगर कहीं भी अच्छा अभ्यास हो रहा है, तो उसको अपनाने में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार का काम एक लेवल प्लेइंग फील्ड (समान अवसर प्रदान करना) देना है और आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। लेकिन खेलना तो आप लोगों को ही है। खेल का अभ्यास भी करते रहिए। मैं चाहता हूं आप ऐसा खेलें कि पूरी दुनिया दर्शक बनकर आपकी ओर देखे। राजनाथ सिंह ने कहा, हाल ही में पहलगाम हमले के बाद जिस तरह हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि, हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह तैयार थीं। लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में शांति और कानून-व्यवस्था में अनिश्चितता तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हर डेवेलप का सावधानी से विश्लेषण करते हुए अपने कदम उठाने होंगे। आज रक्षा और युद्ध क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे केवल स्वदेशीकरण के माध्यम से ही निपटा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, यह भी मैं कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मैं आप सबके बीच आया हूं। तो उससे संबंधित कुछ बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारी सेनाओं के साथ-साथ आप सभी औद्योगिकी योद्धाओं को भी हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने कहा, हम सबने देखा कि आकाश मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली और अन्य कई प्रकार के स्वदेशी उपकरणों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपना पराक्रम दिखाया। हमारे स्वदेशी उपकरणों की सफलता ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की साख, भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारी सेनाओं के साथ-साथ उन सबको जाता है, जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे उद्योग योद्धाओं ने नवाचार, डिजाइन और विनिर्माण के मोर्चे पर अथक परिश्रम किया है, आप भी इस जीत के समान रूप से हकदार हैं।

जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई गवई ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

नई दिल्ली । चीफ जस्टिस बीआर गवई ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल, सीजेआई गवई 23 नवंबर को पद से मुक्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख बनने की कतार में अगले स्थान पर हैं।

नियुक्ति के बाद, न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी, 2027 तक लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। 10 फरवरी 1962 को हिसार जिले के पेटवार गांव में जन्मे सूर्यकांत का बचपन साधारण परिवेश में बीता। उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से पूरी की और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिसार से 1981 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से 1984 में कानून (एलएलबी) की पढ़ाई पूरी की। इसी वर्ष उन्होंने हिसार के जिला न्यायालय में वकालत शुरू की और 1985 में चंडीगढ़ स्थित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की। जल्द ही उन्होंने सांविधानिक, सेवा और नागरिक मामलों में अपनी गहरी समझ और सशक्त दलीलों से पहचान बनाई। उनकी न्यायिक यात्रा सामाजिक मुद्दों से जुड़ी रही। वे सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षण, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, पीड़ितों के अधिकार, आरक्षण और सांविधानिक संतुलन जैसे विषयों में संवेदनशील दृष्टिकोण रखते रहे। उनके फैसलों ने सामाजिक न्याय, सांविधानिक मर्यादा और नागरिक अधिकारों को मजबूती दी। 7 जुलाई 2000 को वे हरियाणा के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुए। यह पद संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। अगले वर्ष उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता (सीनियर एडवोकेट) का दर्जा मिला।

राजस्थान, एमपी, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में होगा एसआईआर

नई दिल्ली ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की। इस चरण में 12 राज्यों में मतदाता सूची को अपडेट करने, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने का कार्य किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "आज हम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा करने के लिए उपस्थित हैं। मैं बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाकर इसे सफल बनाया। मैं सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं।

सोमवार रात फ्रीज हुई वोटर लिस्ट; आज से प्रोसेस शुरू, सात फरवरी तक चलेगी

सभी राथों के साथ हुई चर्चा

ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग ने देश के 36 राथों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों के साथ बैठकें कीं और एसआईआर प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मतदाता सूची की गुणवत्ता और सटीकता को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

अब तक 8 बार हो चुका है एसआईआर

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी कि 1951 से 2004 के बीच देश में आठ बार विशेष गहन पुनरीक्षण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने कई मौकों पर मतदाता सूचियों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके जवाब में यह कदम उठाया जा रहा है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि आगामी चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

आज रात फ्रीज कर दिया जाएगा वोटर लिस्ट

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि निर्वाचक सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया वाले राथों में मतदाता सूची को आज रात फ्रीज कर दिया जाएगा।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि कई वजहें हैं, जिनके कारण यह कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है।

इन राथों होगा एसआईआर का दूसरा चरण

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण देश के 12 राथों और केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। इनमें अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कल से इन राथों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल पांच राथों–पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी–में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।